आई/89656/2021 फाइल नं0-23-10099(099)/137/2021-23-10-2021

संख्या-78/2021/563/23-10-21-165वी0वी0एन0/2013

प्रेषक,

राजेश कुमार अग्रवाल,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास)/विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-10 लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं0-57 एवं अनुदान सं0-83 के अंतर्गत जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन लोहिया पथ पर 08 लेन आर0ओ0बी0 के अंत में पिकप भवन के निकट एक अन्य एल शेप उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु पुन: पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र संख्या-339/लखनऊ/पुन0अ0/बी0एम0 सी0/16 दिनांक 24.05.2016 एवं तदक्रम में पत्र संख्या-05/आर0ओ0बी0/मध्य क्षेत्र/बी0एम0सी0/2021 दिनांक 07-04-2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन लोहिया पथ पर 08 लेन आर0ओ0बी0 के अंत में पिकप भवन के निकट एक अन्य एल शेप उपरिगामी सेतु हेतु पुनरीक्षित प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त सेतु की मूल स्वीकृति उ0प्र0 व्यापार विकास निधि योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2013-14 में शासनादेश सं0-487/23-10-14-165 वीवीएन0/13, दि0 26.02.2014 द्वारा रू0 2575.34 लाख की प्रदान की गयी थी। प्रथम पुनरीक्षित शासनादेश सं0-02आ0व्या0वि0नि0/23-10-15-165 वीवीएन0/13, दि0 17.12.2015 द्वारा रू0 2775.34 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल द्वारा प्रश्नगत परियोजना हेतु निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन, निम्नांकित विवरणानुसार लागत रू0 3028.52 लाख (रूपये तीस करोड़ अट्ठाईस लाख बावन हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति सहर्ष प्रदान की जाती हैः-

(धनराशि लाख रूपये में)

| क्रमसं0 | जनपद/कार्य का विवरण | मूल स्वीकृत लागत | प्रथम पुनरीक्षित स्वीकृत लागत | वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वीकृत /पुनरीक्षित लागत |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | जनपद लखनऊ में निर्माणाधीन लोहिया पथ पर 08 लेन आर0ओ0बी0 के अंत में पिकप भवन के निकट एक अन्य एल शेप उपरिगामी सेतु निर्माण हेतु | 2575.34 | 2775.34 | 3028.52 |
| | योग- | 2575.34 | 2775.34 | 3028.52 |

(1) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-बी-2-2528/दस-2014-10/77, दिनांक 26.08.2014 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

(2) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3) कार्य की विशिष्टियां, मानक एवं गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग/कार्यदायी संस्था की होगी। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय।

(4) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा ।

(5) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(6) पुनरीक्षित प्रायोजना प्रस्ताव में कराये गये कार्यों की लागत को यथावत सम्मिलित किया गया है, जिसका समस्त उत्तदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा । प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की मात्राओं को यथावत मानते हुये परीक्षण किया गया है। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व विभागाध्यक्ष/कार्यदायी संस्था का होगा ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(7) अधिष्ठान व्यय/सेन्टेज चार्ज की धनराशि समय-समय पर स्वीकृत/आवंटित की जा रही धनराशि के सापेक्ष ही कार्यदायी संस्था को भुगतान की जायेगी।

(8) लेबर सेस की धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(9) प्रायोजना का निर्माण कार्य पुनरीक्षित लागत में यथा शीघ्र पूर्ण किया जाये। प्रायोजना का भविष्य में अब कोई पुनरीक्षण स्वीकार नहीं होगा।

(10) मूल्य ह्रास निधि की धनराशि सुसंगत लेखाशीर्षक मे जमा करायी जायेगी ।

(11) प्रायोजना की लागत का आंकलन प्रशासकीय/वित्तीय अनुपालन तथा बजट आवंटन के उददेश्य से किया गया है। प्रायोजना पर सक्षम स्तर का तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय ।

(12) विभागाध्यक्ष द्वारा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयररेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा ।

(13) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति के पूर्व विभागाध्यक्ष द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(14) प्रश्नगत परियोजना की मूल स्वीकृत विषयक शासनादेश की शर्तो का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(15) प्रश्नगत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सापेक्ष धनावंटन की कार्यवाही विभागाध्यक्ष से औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्राप्त हो जाने के उपरांत की जायेगी ।

(16) विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये क्षेत्रीय अधिकारी/क्षेत्रीय मुख्य अभियंता उत्तरदायी होंगे।

(17) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021-बी-1-375/दस-2021-231/2021 दिनॉक 22 मार्च 2021 का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(18) भारत सरकार की कोविड-19 हेतु जारी गाइड लाइन्स का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा ।

(19) प्रश्नगत कार्य पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान सं0-58 के अंतर्गत लेखाशीर्षक 5054-सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय-04-जिला तथा अन्य सड़कें-337-सड़क निर्माण कार्य-15-कृषि विपणन सुविधाओं हेतु राजस्व ग्राम/बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु ग्रामीण संपर्क मार्गों का नवनिर्माण/पुनर्निर्माण/मिसिंग लिंक एवं अन्य ग्रामीण मार्गों के चालू कार्यों हेतु एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-8-1403917/दस-2021, दिनांक 12 अगस्त,2021 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

( राजेश कुमार अग्रवाल )
उप सचिव।

संख्या- 78/2021/563(1)/23-10-21,तददिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

(1) महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
(2) मण्डलायुक्त, लखनऊ क्षेत्र /जिलाधिकारी, लखनऊ ।
(3) प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लि0, लखनऊ ।
(4) मुख्य अभियंता(मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
(5) मुख्य अभियंता, मध्य क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
(6) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
(7) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2/
(8) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

( राजेश कुमार अग्रवाल )
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in